

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या-1869/2013/अजमेर

मोहम्मद हुसैन पुत्र श्री आयूबखान
निवासी पुलिस चौकी के सामने,
पुष्कर रोड अजमेर तहसील व जिला अजमेर

...प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये
उप-पंजीयक अजमेर द्वितीय
2. मु. जमना बेवा पन्ना
निवासी ग्राम लोहागल तहसील व जिला अजमेर।
3. सुल्तान सुपुत्र स्व. श्री पन्ना
निवासी ग्राम लोहागल तहसील व जिला अजमेर।
4. अर्जुन सुपुत्र स्व. श्री पन्ना
निवासी ग्राम लोहागल तहसील व जिला अजमेर।

...अप्रार्थीगण

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री कृष्णा गोपाल खत्री

अभिभाषक

श्री आर. के. अजमेरा

उप-राजकीय अभिभाषक

अनुपस्थित

....प्रार्थीया की ओर से

....अप्रार्थी सं. 1 विभाग की ओर से

....अप्रार्थी सं. 2 से 4

निर्णय दिनांक : 17.05.2017

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थीया द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) अजमेर (जिसे आगे 'कलक्टर' कहा गया है) के आदेश दिनांक 25.02.2011 प्रकरण संख्या 673/2010 के विरुद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे 'मुद्रांक अधिनियम' कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने उप-पंजीयक अजमेर द्वितीय द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं 2 लगायत 4 के नाम ग्राम लोहागल पटवार क्षेत्र माकडवाली द्वितीय भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अजमेर प्रथम तहसील व जिला अजमेर में स्थित संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा सं 650 की 5 बीघा 10 बिस्वा 10 बिस्वान्सी किस्म बा.-3 खसरा संख्या

२३७

लगातार.....2

651 की 06 बिस्वा 10 बिस्वान्सी किस्म मरडा, खसरा संख्या 630 की 07 बिस्वा किस्म बरडा, खसरा संख्या 719 की 01 बीघा 15 बीस्वा किस्म बरडा एवं खसरा संख्या 720 की 13 बिस्वा किस्म बा-3 जो कि श्री पन्ना का स्वर्गवास होने के पश्चात उनके विधिक उत्तराधिकारी वारीसार विधिक विरासत नामान्तरण संख्या 407 दिनांक 10.12.2001 स्वीकृत किया जाकर खातेदारी अप्रार्थी संख्या-2 लगायत 4 के नाम पर दर्ज की गई। तदानुसार अप्रार्थी संख्या-2 लगायत 04 जो कि उक्त वर्णित खातेदारी कृषि भूमि के विधिक वारिस हैं से उक्त कृषि भूमि प्रार्थी द्वारा जरिये विक्रय पत्र खरीद किए जाने बाबत दस्तावेज रू. 951000/- मालियत पर पंजीयन हेतु उपपंजीयन अधिकारी - अजमेर द्वितीय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसको कमी मालियत का मानते हुए उपपंजीयन अधिकारी अजमेर द्वितीय द्वारा इसकी मालियत 39,56,000/- तय करते हुए इस पुस्तक संख्या 01 पर जिल्द संख्या 189 में पृष्ठ संख्या 195 क्रम संख्या 2010004391 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 7596 के पृष्ठ संख्या 339 से 395 पर चस्पा कर दिनांक 04.06.2010 को पंजीयन कर प्रार्थी को लौटा दिया गया था जिस हेतु प्रार्थी द्वारा नियमानुसार देय मुद्रांक शुल्क रू. 1,97,800/- पंजीयन शुल्क रू. 39,560/- उपपंजीयन अधिकारी अजमेर द्वितीय के समक्ष जमा करा दिया गया था। उपपंजीयक द्वितीय द्वारा निरीक्षण किया जाकर पंजीबद्ध दस्तावेज को कमी मालियत का मानकर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा मुद्रांक शुल्क वसूलने का आक्षेप अंकित कर रू. 4,06,040/ रू. वसूल करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा कार्यवाही करते हुए कृषि भूमि की मालियत रू. 1,18,68,000/- रू तय कर कमी मुद्रांक शुल्क रू 3,95,600/- तथा कमी पंजीयन शुल्क रू. 10,440/- एवं शास्ति रू 160/- लगाते हुए कुल राशि रू. 4,06,200/- प्रार्थी से वसूल करने के निर्देश दिये गये जिसके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3. निगरानी दर्ज की जाकर रिकार्ड व अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 2 लगायत 4 अनुपस्थित रहे।

4. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है। निर्णय की जानकारी कुर्की वारंट से हुई है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में रेफरेन्स को स्वीकार करने के सम्बन्ध

अ.प.✓

में कोई कारण अंकित नहीं किया गया है। निर्णय नॉन स्पीकिंग व नॉन रीजण्ड है। निर्णय में तर्क, कारण व विवेचना का अभाव है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान मुद्रांक नियम 2003 के नियम 65 की पालना किये बिना व बिना कोई जांच किए रेफरेन्स स्वीकार किया है जो विधिसम्मत नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर रेफरेन्स खारिज किया जावे।

6. राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है, अतः निगरानी खारिज की जावें।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :-

8. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सशपथ होने, निर्णय गुणावगुण के आधार पर श्रेयस्कर होने तथा प्रार्थीया द्वारा धारा 5 में अंकित कारण की निर्णय की जानकारी कुर्की वारण्ट के आधार पर हुई संतोषजनक होने के दृष्टिगत स्वीकार किया जाकर निगरानी अन्दर मियाद मानी जाती है।

9. निगरानी में मुख्य आधार यह है कि निर्णय में रेफरेन्स के बिन्दुओं को बिना कोई विवेचना एवं विश्लेषण किये पारित किया है जो विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में रेफरेन्स को स्वीकार करने के सम्बन्ध में कोई कारण अंकित नहीं किया गया है। निर्णय नॉन स्पीकिंग व नॉन रीजण्ड है। निर्णय में तर्क, कारण एवं विधिक विवेचना का अभाव है।

कलक्टर (मुद्रांक) अजमेर के निगरानीधीन आदेशों के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि कलक्टर (मुद्रांक) ने रेफरेन्स के तथ्यों की विवेचना किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेफरेन्स रेफरेन्स स्वीकार किये जाने का कोई आधार स्पष्ट नहीं किया है व न ही रेफरेन्स के तथ्यों के संबंध में कोई जांच की गई है। अधीनस्थ न्यायालय का दायित्व बनता है कि उसके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में उठाये गये बिन्दुओं की विवेचना करने के उपरान्त ही उन्हें मानने या न मानने पर तथ्यों पर आधारित अपना मत प्रकट करते, जिससे अपीलीय अधिकारी के आदेश/निर्णय के विरुद्ध अपील होने पर सम्बन्धित न्यायालय अपना निर्णय पारित करें कि अवर अधिकारी का निर्णय न्याय संगत है अथवा नहीं किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय का दायित्व बनता है कि वह सचेतन

an✓

मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए निष्पक्ष अभिव्यक्ति दें। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ के सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वर्क्स कान्स्ट्रैक्ट एवं लीजिंग टैक्स, कोटा बनाम मैसर्स शुक्ला एंड ब्रदर्स (Civil Appeal No. Nil of 2010/S.L.P.(C)No. 16466 of 2009), date 15.4.2010) में पारित किय गये निर्णय के कुछ अंश उद्धृत किया जाना उक्त परिप्रेक्ष्य में समीचीन होगा :-

".... To subserve the purpose of justice delivery system therefore, it is essential that the Courts should record reasons for its conclusions whether disposing of the case at admission stage or after regular hearing."

"A litigant has legitimate expectation of knowing reasons for rejection of his claim/payer. It is then alone, that a party would be in a position to challenge the order on appropriate grounds. As arguments bring things hidden and obscure to the light of reasons, reasoned judgment where the law and factual matrix of the case it discussed provided lucidity and foundation for conclusions or exercise of judicial discretion by the Courts. Reason is the very life of law. When the reason of a law once ceases, the law itself generally ceases. Such is the significance of reasoning in any rule of law. Giving reasons furthers the cause of justice as well as avoids uncertainty. As a matter of fact it helps in the observance of law of precedent. Absence of reasons on the contrary essentially introduces an element of uncertainty, dissatisfaction and give entirely different dimensions to the questions of law raised before the higher appellate Courts. When reasons are announced and can be weighed, the public can have assurance that process of correction is in place and working. It is requirement of law that correction process of judgments should not only appear to be implemented but also to have been properly implemented. Reasons for an order would ensure and enhance public confidence and would provide due satisfaction to the consumer of justice under our justice dispensation system." उपरोक्त विधिक धारणा से भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है।

10. अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि निगरानीधीन निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है तथा यदि प्रकरण में निगरानीधीन आदेश निरस्त किया जाकर प्रतिप्रेषित किया जाता है तो न्यायिक दृष्टिकोण से प्रार्थी को सुनवाई का भी समुचित अवसर मिल सकेगा।

11. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विवेचना-विश्लेषण सहित निर्णय पारित नहीं करने के कारण विधिसम्मत नहीं होने के कारण निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निगरानीधीन आदेश निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए, राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 2004 के नियम 65 की पालना करते हुए पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए पुनः नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.06.2017 को पेश हों।

12. निर्णय सुनाया गया।

(नैथूराम)
सदस्य